



make my trip
HOTELS UNLIMITED

Budget Friendly Thailand
4 Nights | 5 Days

Starting ₹23,990*

BOOK NOW

*T&C Apply

कुपोषण मिटाने के नाम पर हो रहा काला कारोबार

- ♦ स्वास्थ्य नीतियों पर भी कंपनियों के कब्जे का खतरा, प्रधानमंत्री की समिति के सदस्य ने किया आगाह
- ♦ एनएसी सदस्य भी कर चुकीं है विरोध

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

रसोई में बने खाने की जगह चोर दरवाजे से फैक्ट्री के सामान को दिलवाने की कोशिश तेज हो गई है। यह हो रहा है बच्चों में कुपोषण दूर करने के नाम पर। विशेषज्ञों ने इस बारे में प्रधानमंत्री को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी नीतियां बनाने में इन कंपनियों की भागीदारी को पहली बार खुली मंजूरी दी जा रही है।

पोषण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'बच्चों के संरक्षण पर सक्रियता का आह्वान' (चाइल्ड सर्वाइवल काल टू एक्शन) के नाम से निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीति तैयार की है। लेकिन अब 'भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की समिति' के सदस्य अरुण गुप्ता सहित चार दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को आगाह किया है। गुप्ता कहते हैं कि पोषण संबंधी नीतियां बनाने में

उन पक्षों को किसी कीमत पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिनका स्वार्थ इससे जुड़ा है। बिस्किट से लेकर कई तरह के फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां इन नीतियों को प्रभावित करने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस योजना का विरोध करने वालों में संग्रम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की सदस्य अरुणा राय और इसके पूर्व सदस्य ज्यां ड्रेज भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन स्केलिंग अप न्यूट्रीशन (सन) मूवमेंट की गतिविधियों को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया है। इस समय 'सन' के अंतरराष्ट्रीय संयोजक डेविड नबरो भासत में योजना आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय आदि के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जबकि 'ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया' ने चेताया है कि सन मूवमेंट निजी क्षेत्र के साथ सरकारी भागीदारी के नाम पर इन कंपनियों की फैक्ट्री में बने उत्पादों को बाजार दिलाने में मदद करता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि मिड डे मील या ऐसे किसी दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रम में बिस्किट या ऐसे किसी खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं किया जा सकता।

यात्रा के दौरान अपना ईमेल प्राप्त करें

अभी साइन अप करें

Google

Superb watches under ₹999

Shop NOW

